PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 068
दि. 07.07.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

करूर भगदड़ जांच में नया मोड़: मंत्रियों पर गवाहों को प्रभावित करने के आरोप, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

चेन्नई/नई दिल्ली। तमिलनाडु के बहुचर्चित करूर भगदड़ मामले की जांच एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है। मामले में गवाहों को प्रभावित किए जाने के गंभीर आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट> मंगलवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस मामले के कुछ आरोपी, जो वर्तमान राज्य सरकार में मंत्री हैं, जांच को प्रभावित करने और गवाहों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इन आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य पाए जाते हैं तो अदालत जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश जारी कर सकती है। ऐसे में मंगलवार की सुनवाई को पूरे मामले की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।

मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने अदालत का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि यद्यपि मामले की जांच पहले से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कर रही है, लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रभावशाली लोग गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते ऐसे प्रयासों पर रोक नहीं लगी तो निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने मामले को अगले ही दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

यह मामला न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति शील नागू की आंशिक कार्यदिवस पीठ के समक्ष आया। पीठ ने कहा कि याचिका में लगाए

गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, इसलिए इस पर विस्तृत सुनवाई आवश्यक है। अदालत मंगलवार को यह भी विचार करेगी कि क्या गवाहों की सुरक्षा और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपायों की आवश्यकता है।

याचिका में दावा किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो वर्तमान तमिलनाडु सरकार में मंत्री पद पर हैं। आरोप है कि वे अपने प्रभाव का उपयोग कर गवाहों के बयान प्रभावित करने या उन्हें दबाव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की ओर से अभी विस्तृत जवाब सामने आना बाकी है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि यदि समय रहते अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है तो पूरी जांच की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

करूर भगदड़ मामला पिछले वर्ष देशभर में चर्चा का विषय बना था। इस दर्दनाक हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अनेक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद जांच को लेकर कई सवाल उठे थे और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई थी। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 13 अक्तूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच राज्य पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का ऐतिहासिक आदेश दिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि घटना की गंभीरता और जनहित को देखते हुए स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच कराया जाना आवश्यक है ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट ने उस समय यह भी स्पष्ट किया था कि इतनी बड़ी त्रासदी केवल एक राज्य का विषय नहीं, बल्कि पूरे देश की संवेदनशीलता से जुड़ा मामला है। इसलिए जांच किसी भी प्रकार के राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने का सबसे प्रभावी माध्यम है।

सीबीआई जांच की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय निगरानी समिति का भी गठन किया था। इस समिति का दायित्व जांच की प्रगति पर नजर रखना और यह सुनिश्चित करना है कि जांच निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष ढंग से आगे बढ़े। अदालत ने उस समय तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) और एक सदस्यीय जांच आयोग की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह सीबीआई को सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराए।

यह आदेश उस याचिका पर दिया गया था जिसमें मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलनाडु विजय पार्टी (TVK) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। याचिका में कहा गया था कि मामले की निष्पक्ष जांच केवल स्वतंत्र एजेंसी ही कर सकती है और राज्य स्तर पर गठित जांच तंत्र से लोगों का भरोसा कमजोर हुआ है।

अब गवाहों को प्रभावित किए जाने के आरोप सामने आने के बाद यह मामला फिर से न्यायिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अदालत को प्रथम दृष्टया यह महसूस होता है कि गवाहों पर दबाव डाला जा रहा है या जांच में हस्तक्षेप हो रहा है, तो वह सीबीआई को गवाहों की सुरक्षा बढ़ाने, आरोपों की अलग से जांच करने अथवा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे सकती है। अदालत यह भी देख सकती है कि क्या निगरानी समिति को अतिरिक्त अधिकार या विशेष निर्देश देने की आवश्यकता है।

कर्नाटक की मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सियासी घमासान: एनडीए ने चुनाव आयोग से की जांच की मांग, एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल

बेंगलुरु। कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी वी. अंबुकुमार से मुलाकात कर विस्तृत शिकायत सौंपी और एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

एनडीए नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में से एक है और इसका उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित तथा विश्वसनीय बनाना होता है। लेकिन राज्य में जिस प्रकार से यह अभियान संचालित किया जा रहा है, उससे इसकी निष्पक्षता प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि पुनरीक्षण कार्य में लगे कई अधिकारी और कर्मचारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे पूरी कवायद का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है।

शिकायत पत्र में दावा किया गया कि अनेक स्थानों पर मतदाता गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार घर-घर जाकर भरवाने के बजाय सामुदायिक भवनों, मस्जिदों तथा कुछ बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के निजी आवासों पर भरवाए जा रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि यह तरीका चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत है और इससे मतदाता सत्यापन प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर अभियान को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में व्हाट्सएप समूह बनाए गए, जिनके माध्यम से लोगों को विशेष स्थानों पर जाकर अपने प्रपत्र भरने के लिए प्रेरित किया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकार की व्यवस्था आधिकारिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है और इससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लग सकता है।

एनडीए नेताओं ने पत्र में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने वाला अभियान है। यदि इसमें निर्धारित नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन होता है तो इसका सीधा असर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली से भविष्य में एक ऐसी मतदाता सूची तैयार होने का खतरा है, जिसकी प्रमाणिकता पर सवाल उठ सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव अधिकारी से मांग की कि पूरे मामले की तत्काल उच्चस्तरीय जांच कराई जाए और अब तक भरे गए सभी गणना प्रपत्रों का घर-घर जाकर पुनः सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। उनका कहना है कि प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि सूची में शामिल सभी नाम वास्तविक और पात्र मतदाताओं के हैं।

एनडीए नेताओं ने यह भी मांग उठाई कि यदि जांच में किसी अधिकारी, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है और ऐसे मामलों में जवाबदेही तय होना आवश्यक है।

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि एसआईआर अभियान का मूल उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और विश्वसनीय बनाना है, लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो यह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा।

फिलहाल मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय की ओर से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की गई है, हालांकि आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निर्वाचन प्रशासन इन आरोपों की जांच के लिए क्या कदम उठाता है और क्या मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में अतिरिक्त सत्यापन या अन्य सुधारात्मक उपाय लागू किए जाते हैं। कर्नाटक में आगामी चुनावी गतिविधियों को देखते हुए यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

नीरव मोदी की सभी कानूनी राहें बंद: यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय से भी राहत नहीं, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता पूरी तरह साफ

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के कथित बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को अपनी अंतिम कानूनी लड़ाई में भी बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ECHR) ने उसकी अंतिम याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उसके भारत प्रत्यर्पण के रास्ते में मौजूद सभी कानूनी बाधाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। अब मामला केवल ब्रिटेन और भारत के बीच प्रशासनिक औपचारिकताओं तक सीमित रह गया है। सूत्रों के अनुसार ब्रिटेन सरकार ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है और इस संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ आवश्यक राजनयिक समन्वय जारी है।

रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिटेन की सभी अदालतों में अपनी अपीलें खारिज होने के बाद नीरव मोदी ने अप्रैल 2026 में अंतिम उम्मीद के तौर पर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उसने अदालत से अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने और अंतरिम राहत देने की मांग की थी। हालांकि अदालत ने उसकी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और न तो कोई अंतरिम आदेश जारी किया और न ही प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर रोक लगाई। इस फैसले के साथ ही प्रत्यर्पण को चुनौती देने का उसका अंतिम कानूनी विकल्प भी समाप्त हो गया है। नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की एचएमपी वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। गिरफ्तारी के बाद से उसने ब्रिटेन की विभिन्न अदालतों में कई बार जमानत और प्रत्यर्पण रोकने के लिए याचिकाएं दायर कीं, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। वर्ष 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश गृह सचिव प्रीति पटेल ने भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भी उसने विभिन्न कानूनी आधारों पर कार्रवाई रोकने का प्रयास जारी रखा।

मार्च 2026 में नीरव मोदी ने एक बार फिर अदालत में यह दावा किया था कि भारत भेजे जाने पर उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश न्यायालयों ने इन दलीलों को पर्याप्त आधार नहीं माना और उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसने यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में अंतिम अपील दायर की थी, जिसे भी अब अस्वीकार कर दिया गया है।

नीरव मोदी भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक माने जाने वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का प्रमुख आरोपी है। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से बिना पर्याप्त सुरक्षा के फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) जारी करवाए। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विदेशी बैंकों से भारी धनराशि प्राप्त की गई, जिससे बैंक को लगभग दो अरब अमेरिकी डॉलर (करीब 14 हजार करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। इस मामले में भारत की जांच एजेंसियां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रही हैं। उसके खिलाफ भारत में धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई गंभीर मामलों की जांच चल रही है।

प्रत्यर्पण मामले के अलावा नीरव मोदी को ब्रिटेन में एक अलग वाणिज्यिक मुकदमे में भी बड़ा झटका लगा है। लंदन के सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दुबई स्थित फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए ऋण के संबंध में व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर वह बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 11.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर (ब्याज सहित) चुकाने के लिए जिम्मेदार है। अदालत ने बैंक के मांग नोटिस को वैध माना और कहा कि भारतीय कानून के तहत दी गई गारंटी पूरी तरह लागू होती है। यह फैसला नीरव मोदी की कानूनी स्थिति को और कमजोर करने वाला माना जा रहा है।

अब जबकि सभी न्यायिक विकल्प समाप्त हो चुके हैं, प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतिम प्रशासनिक चरण में पहुंच गई है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां दस्तावेजों के सत्यापन, यात्रा संबंधी औपचारिकताओं और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। आधिकारिक तौर पर प्रत्यर्पण की तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही नीरव मोदी को भारत लाया जा सकता है।

यदि प्रत्यर्पण प्रक्रिया निर्धारित योजना के अनुसार पूरी होती है, तो नीरव मोदी को भारत लाकर विशेष अदालतों के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां पीएनबी घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में उसके खिलाफ लंबित मुकदमों की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लंबे समय से लंबित इस मामले में यह घटनाक्रम भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है और इससे देश के सबसे चर्चित आर्थिक अपराध मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है।

भारतीय रेलवे के हरित युग की शुरुआत: 17 जुलाई को दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे स्वच्छ और आधुनिक परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का शुभारंभ होगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन हरियाणा के जींद–सोनीपत रेलखंड पर संचालित होगी और इसे भारतीय रेलवे की हरित परिवहन नीति के तहत विकसित की गई सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना न केवल देश की तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करेगी, बल्कि भविष्य में स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन की दिशा भी तय करेगी।

यह ट्रेन पूरी तरह 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत विकसित की गई है। इसके डिजाइन का विकास अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (RDSO) ने किया है, जबकि इसका निर्माण चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में किया गया है। रेलवे का कहना है कि परियोजना में अधिकतम स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे भारत अब उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने हाइड्रोजन आधारित रेल तकनीक विकसित की है।

उद्घाटन से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जींद पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। रेलवे और राज्य प्रशासन संयुक्त रूप से उद्घाटन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। सुरक्षा, स्टेशन प्रबंधन और तकनीकी परीक्षणों को

लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम से संचालित होगी। इसमें 1200 किलोवाट की दो ड्राइविंग पावर यूनिट्स और आठ आधुनिक यात्री कोच लगाए गए हैं। रेलवे के अनुसार एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद यह ट्रेन लगभग 250 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेगी। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान इसकी गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, जबकि भविष्य में परिचालन परिस्थितियों के अनुसार इसकी गति और क्षमता में वृद्धि की जा सकती है।

हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक को दुनिया की सबसे स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में माना जाता है। इस तकनीक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन के मोटर संचालित होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन नहीं होता। केवल जलवाष्प और ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे शून्य-उत्सर्जन (Zero Emission) परिवहन प्रणाली की श्रेणी में रखा जाता है। रेलवे का मानना है कि भविष्य में डीजल ट्रेनों के विकल्प के रूप में यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सुरक्षा के लिहाज से भी इस ट्रेन को अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस किया गया है। ट्रेन में हाइड्रोजन लीकेज डिटेक्टर, फायर डिटेक्शन सिस्टम, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, स्वचालित नियंत्रण इकाइयां तथा हाइड्रोजन भंडारण के लिए विशेष रूप से सुरक्षित सिलेंडर लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की गैस रिसाव या तकनीकी गड़बड़ी की स्थिति में चेतावनी प्रणाली तुरंत सक्रिय हो जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर ट्रेन की ऊर्जा आपूर्ति स्वतः नियंत्रित की जा सकेगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सभी सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच और रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

जींद और सोनीपत के बीच लगभग 90 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर यह ट्रेन छह स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे ने आम यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इसका किराया भी बेहद किफायती रखा है। इस मार्ग पर न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम 25 रुपये निर्धारित किया गया है। वर्तमान में इसी रूट पर चलने वाली डीजल मल्टीपल यूनिट (डीएमयू) ट्रेन को यह दूरी तय करने में लगभग दो घंटे का समय लगता है, जबकि नई हाइड्रोजन ट्रेन से यात्रा अधिक सुगम और समयबद्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है।

रेलवे के अनुसार इस ट्रेन में लगभग 2,500 यात्रियों के यात्रा करने की क्षमता होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 89 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। भविष्य में तकनीकी उन्नयन के बाद इसकी अधिकतम परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचाई जा सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना भारत में हरित रेल परिवहन के नए युग की शुरुआत साबित हो सकती है।

हाइड्रोजन उत्पादन और फ्यूल सेल प्रणाली के संचालन के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता भी आवश्यक होती है। रेलवे ने बताया कि इस परियोजना के लिए प्रति घंटे लगभग 40 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होगी। इसके लिए स्टेशन परिसरों में वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए जल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा ट्रेन में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध हो सकेगी।

भारतीय रेलवे का मानना है कि यह परियोजना केवल एक नई ट्रेन का शुभारंभ नहीं है, बल्कि देश की परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा आधारित भविष्य की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह परियोजना सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में देश के अन्य गैर-विद्युतीकृत रेल मार्गों पर भी हाइड्रोजन आधारित ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है।

संपादकीय

जीवन-रक्षक न्यायिक पहल

कैसी विडंबना है कि जिस जिम्मेदार व्यवहार को शासन-प्रशासन को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए करना चाहिए, उसकी पहल अदालत को करनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जरूरी नागरिक समस्या की ओर शासन-प्रशासन का ध्यान दिलाया है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है- सड़कों के किनारे छोड़े गए दुर्घटनाग्रस्त वाहन। जिनसे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। दरअसल, शिमला एयरपोर्ट तक जाने वाली सड़क और जिला अदालत के आस-पास पड़ी अनेक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को देखकर ही अदालत ने यह बात कही। कोर्ट का कहना है कि ये दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां सड़क सुरक्षा के लिये खतरा और पर्यावरण के लिये नुकसानदेह हैं। निस्संदेह,यह प्रशासनिक लापरवाही का जीता-जागता उदाहरण है। पहाड़ी राज्यों में, जहां सड़कें संकरी और घुमावदार होती हैं और लगातार भूस्खलन का खतरा बना रहता है, वहां सड़क की हर इंच जगह कीमती होती है। तार्किक ही है कि छोड़ी गई गाड़ियां सड़क की चौड़ाई को कम कर देती हैं। वहीं दूसरी ओर तीव्र मोड़ों पर देखने में बाधा डालती हैं। ये आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही में भी बाधक बनती हैं। निस्संदेह, इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में जब फिसलन भरी सड़कों और कम दृश्यता के कारण वाहन चालक पहले ही ड्राइविंग में मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे में सड़कों को कबाड़खाने में तब्दील करने की इजाजत किसी भी कीमत पर नहीं दी जा सकती।

दूसरी तरफ इन दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। इनका पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव भी एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त वाहनों से अक्सर ईंधन, इंजन ऑयल,कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड तथा बैटरी एसिड रिसता रहता है। जिससे मिट्टी तथा जल-स्रोत प्रदूषित हो सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं जैसे पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह के प्रदूषण के दूरगामी घातक प्रभाव हो सकते हैं। निश्चित रूप से पुलिस, परिवहन विभाग, नगर निकायों, बीमा कंपनियों और न्यायपालिका के बीच तालमेल न होने के कारण ही समस्या जटिल बनी हुई है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के संबंध में जांच लंबित होने, बीमा संबंधी विवादों और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिये निर्धारित जगह न होने से यह समस्या जटिल बनी हुई है। इन सभी कारणों से ये दुर्घटनाग्रस्त वाहन सड़कों के किनारे यूं ही पड़े रहते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने समस्या के निदान के लिये एक कारगर एक्शन प्लान की मांग की है। जिसमें जब्त वाहनों के लिये खास यार्ड बनाने, डिजिटल तरीके से पड़ताल, जब्त वाहनों को छोड़ने के लिये समयबद्ध प्रक्रिया और स्क्रैपिंग सेंटरों के जरिये वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग की सख्त जरूरत है। देश की शीर्ष अदालत ने भी बार-बार कहा है कि जब्त गाड़ियों को अनिश्चित समय के लिये सड़कों पर सड़ने के लिये नहीं छोड़ा जा सकता। सड़क सुरक्षा के मायने सिर्फ ट्रैफिक नियमों को लागू करवाना या संरचना को बेहतर बनाना ही नहीं है। वास्तव में लोगों की जान बचाने के लिये दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सार्वजनिक स्थानों से हटाना भी एक बुनियादी प्रशासनिक जिम्मेदारी है।

Indonesia की धरती पर PM Modi के कदम रखते ही जो हुआ, उसे देखकर पूरी दुनिया को चौंकना ही था

"इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य के आसपास स्थित यह देश विश्व व्यापार की धुरी माना जाता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण जकार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी बन चुका है।

जकार्ता की सरजमीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ भव्य स्वागत बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की बढ़ती रणनीतिक हैसियत का खुला संकेत था। साथ ही जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए खुद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो हवाई अड्डे पर पहुँचे वह दोनों देशों के बीच की घनिष्ठता को दर्शाता है। खास बात यह भी रही कि जब प्रधानमंत्री का विमान इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, तो इंडोनेशिया वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने उनके विमान के साथ उड़ान भरी। हम आपको बता दें कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में तेज होती कूटनीतिक खींचतान, समुद्री प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा और आर्थिक गठबंधनों की नई बिसात के बीच मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा को भारत की उभरती वैश्विक रणनीति के निर्णायक अभियान के तौर पर देखा जा रहा है। मोदी का जकार्ता से लेकर मेलबर्न और ऑकलैंड तक का यह दौरा सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार नहीं, बल्कि हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत में भारत की बढ़ती राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक मौजूदगी का प्रभावशाली प्रदर्शन भी माना जा रहा है।

हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का पहला पड़ाव इंडोनेशिया है, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टि का सबसे अहम स्तंभ बनकर उभरा है। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा इसलिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि वर्ष 2018 में दोनों देशों के संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद अब दोनों पक्ष प्रतीकात्मक मित्रता से आगे बढ़कर ठोस सामरिक और आर्थिक परिणामों की दिशा में बढ़ना चाहते हैं।

देखा जाये तो इंडोनेशिया की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मलक्का जलडमरूमध्य के आसपास स्थित यह देश विश्व व्यापार की धुरी माना जाता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों पर स्थित होने के कारण जकार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की राजनीति का केंद्रीय खिलाड़ी बन चुका है। ऐसे में भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग का बढ़ना सीधे तौर पर चीन की बढ़ती समुद्री महत्वाकांक्षाओं के मुकाबले सामरिक संतुलन तैयार करने की दिशा में देखा जा रहा है। मोदी और प्रबोवो के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा सहयोग, समुद्री निगरानी, डिजिटल संपर्क, व्यापार और महत्वपूर्ण खनिजों पर व्यापक चर्चा होगी। दुनिया के निकेल भंडार का बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया के पास है। इसके अलावा तांबा, टिन और बॉक्साइट जैसे खनिज भी वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। भारत के विद्युत वाहन, हरित ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह साझेदारी बेहद अहम मानी जा रही है। देखा जाये तो यह केवल व्यापार नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की तकनीकी और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में भारत की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है।

रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के रिश्ते लगातार गहरे हुए हैं। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने सैन्य तालमेल को नई मजबूती दी है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली को लेकर चल रही चर्चाएं भी दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का संकेत मानी जा रही हैं। मलक्का क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंद महासागर में किसी भी सामरिक अस्थिरता का सीधा असर भारत की ऊर्जा और व्यापारिक आपूर्ति पर पड़ सकता है।

मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का सांस्कृतिक पक्ष भी बेहद प्रभावशाली रहने वाला है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ योग्यकर्ता स्थित प्रांबनन मंदिर परिसर जाएंगे, जो भगवान शिव को समर्पित दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े मंदिर परिसरों में शामिल है। यह यात्रा भारत और इंडोनेशिया के हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्तों को नई कूटनीतिक ऊर्जा देने का प्रयास भी मानी जा रही है।

इंडोनेशिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां उनकी बातचीत का केंद्र हिंद प्रशांत क्षेत्र की सामरिक स्थिरता और आर्थिक साझेदारी होगी। पिछले पांच वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों ने जिस तेजी से नई ऊंचाई हासिल की है, वह वैश्विक राजनीति में बदलते समीकरणों का स्पष्ट संकेत है। अब दोनों देश केवल मित्र राष्ट्र नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार के रूप में उभर चुके हैं।

मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति दी है। भारतीय निर्यातकों को लगभग पूर्ण शुल्क मुक्त पहुंच मिलने के बाद व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस साझेदारी का सबसे बड़ा सामरिक पक्ष यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का विकल्प तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग भविष्य की भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा में दोनों देशों को मजबूत स्थिति में ला सकता है।

रक्षा सहयोग भी इस रिश्ते की सबसे मजबूत धुरी बन चुका है। मालाबार नौसैनिक अभ्यास, वार्षिक रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद और क्वॉड मंच पर बढ़ती सक्रियता हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। समुद्री सुरक्षा, साइबर सहयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ती साझेदारी यह स्पष्ट कर रही है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अब क्षेत्रीय स्थिरता के साझा संरक्षक बनते जा रहे हैं।

मेलबर्न में भारतीय समुदाय के साथ होने वाला मोदी का संवाद भी राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारतीय प्रवासी अब दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सेतु बन चुके हैं। शिक्षा और पेशेवर अवसरों के माध्यम से भारतीय युवाओं की बढ़ती मौजूदगी ऑस्ट्रेलिया में भारत की साख को मजबूत कर रही है।

प्रधानमंत्री की तीन देशों की यात्रा का अंतिम चरण न्यूजीलैंड रहेगा, जो ऐतिहासिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से बेहद अहम माना जा रहा है। लगभग चार दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह द्विपक्षीय यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता नई आर्थिक संभावनाओं का द्वार खोल चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच होने वाली वार्ता में व्यापार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत स्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय वस्तुओं को पूर्ण शुल्क मुक्त पहुंच देने का फैसला भारत के लिए बड़ी आर्थिक उपलब्धि माना जा रहा है। वहीं भारत ने अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा करते हुए संतुलित व्यापार नीति अपनाकर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि वह आर्थिक विस्तार के साथ घरेलू हितों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देगा।

प्रेरणा

त्याग का प्रकाश: संन्यासी का जीवन क्यों बनता है समाज के लिए सर्वोच्च प्रेरणा

संन्यास केवल वस्त्र बदल लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और आत्मा के पूर्ण परिवर्तन का मार्ग है। एक सच्चा संन्यासी संसार से भागता नहीं, बल्कि संसार को सही दिशा दिखाने के लिए अपने जीवन को तप, त्याग और अनुशासन का उदाहरण बना देता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार, व्यवसाय और जिम्मेदारियों के बीच जीवन जीता है, इसलिए उसके लिए कुछ सीमित इच्छाएं और सुविधाएं स्वाभाविक मानी जाती हैं। लेकिन संन्यासी का जीवन सामान्य मनुष्य से अलग होता है। उसका प्रत्येक कार्य, प्रत्येक विचार और प्रत्येक आचरण समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। यही कारण है कि संन्यासियों के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं। ये नियम उन्हें कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें आत्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने और समाज के लिए आदर्श बनाने के उद्देश्य से निर्धारित किए गए हैं। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य ने अपने गुरु परमहंसजी से यही प्रश्न किया कि जब सामान्य लोग जीवन की सभी सुख-सुविधाओं का उपयोग करते हैं, तब संतों और संन्यासियों के लिए इतने कठोर नियम क्यों बनाए गए हैं? क्या वे भी इंसान नहीं हैं? क्या उन्हें सामान्य जीवन जीने का अधिकार नहीं है? यह प्रश्न केवल उस शिष्य का नहीं था, बल्कि हर उस व्यक्ति के मन का प्रश्न है जो संन्यास के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। परमहंसजी ने बड़े सरल लेकिन गहन शब्दों में उत्तर दिया कि संन्यासी का जीवन केवल उसका अपना जीवन नहीं होता, बल्कि वह पूरे समाज की धरोहर होता है। इसलिए उसका प्रत्येक कदम दूसरों के लिए शिक्षा बन जाता है। परमहंसजी ने समझाया कि समाज में रहने वाला सामान्य व्यक्ति परिवार, व्यवसाय और सामाजिक कर्तव्यों के साथ जीवन बिताता है। उसे अपने जीवन के निर्वाह के लिए धन कमाना पड़ता है, परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है और अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। लेकिन जिसने संन्यास ग्रहण किया है, उसने स्वयं अपने मन से इन सभी सांसारिक बंधनों का त्याग किया है। इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि वह स्त्रियों से अनावश्यक निकटता से बचे, धन का संग्रह न करे, सुख-सुविधाओं की लालसा न रखे और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से स्वयं को दूर रखे। यदि संन्यासी भी सामान्य मनुष्य की तरह इच्छाओं और संग्रह में डूब जाएगा, तो फिर समाज को त्याग का मार्ग कौन दिखाएगा? संन्यासी का सबसे बड़ा धर्म उसका आचरण होता है। उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं वैसा जीवन जीना अत्यंत कठिन होता है। समाज केवल शब्दों से नहीं बदलता, बल्कि उदाहरणों से बदलता है। जब लोग किसी संत को कठिन परिस्थितियों में भी शांत, संतुष्ट और संयमित देखते हैं, तब उन्हें विश्वास होता है कि आत्मिक शांति वास्तव में संभव है। यदि संत स्वयं क्रोध, लालच और भोग-विलास में डूब जाए, तो उसके उपदेशों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए संन्यासी का जीवन जितना कठोर दिखाई देता है, उतना ही प्रेरणादायक भी होता है। त्याग का अर्थ केवल वस्तुओं को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उनके प्रति मन के आकर्षण को समाप्त करना है। अनेक लोग बाहरी रूप से साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उनके भीतर इच्छाओं का समुद्र उमड़ता रहता है। दूसरी ओर सच्चा संन्यासी महलों में भी रहे तो उसका मन किसी वस्तु में आसक्त नहीं होता। वह जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख कभी भी स्थायी नहीं होते। जो आज हमारे पास है, वह कल किसी और का हो सकता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो इन अस्थायी वस्तुओं के पीछे अपना पूरा जीवन नष्ट न करे।

मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होतीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। यही क्रम जीवन भर चलता रहता है। इच्छा पूरी होने पर थोड़ी देर का सुख मिलता है, लेकिन नई इच्छा फिर मन को बेचैन कर देती है। इस प्रकार मनुष्य का जीवन संतोष के बजाय असंतोष का शिकार हो जाता है। संन्यासी अपने जीवन से यही संदेश देता है कि इच्छाओं का अंत इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, बल्कि त्याग से होता है। जब मन में संतोष का भाव जागता है, तभी वास्तविक आनंद प्राप्त होता है।

संतों का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है और वह संबंधों, सम्मान तथा मानसिक शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए संन्यासी अपने मन को शांत रखने का निरंतर अभ्यास करता है। वह अपमान, आलोचना और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ता। उसका यह धैर्य समाज को सिखाता है कि कठिन समय में संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है।

धन का संग्रह न करने का नियम भी अत्यंत गहरा संदेश देता है। धन स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन धन के प्रति अत्यधिक मोह मनुष्य को स्वार्थी बना देता है। जब व्यक्ति संग्रह की प्रवृत्ति में डूब जाता है, तब उसके भीतर सेवा, दया और करुणा जैसे गुण कमजोर पड़ने लगते हैं। संन्यासी समाज को यह बताता है कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि सद्गुण, संतोष और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। जो व्यक्ति इन गुणों को प्राप्त कर लेता है, वह परिस्थितियां कैसी भी हों, भीतर से समृद्ध बना रहता है।

संन्यास का मार्ग पलायन का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मविजय का मार्ग है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक अर्थ में विजेता कहलाता है। बाहरी युद्ध जीतना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है, लेकिन अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन साधना है। संन्यासी इसी आंतरिक विजय का प्रतीक होता है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करने में है।

आज का आधुनिक समाज भौतिक प्रगति के शिखर पर पहुंच चुका है, लेकिन मानसिक तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और असंतोष भी पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गए हैं। ऐसे समय में संतों और संन्यासियों का जीवन पहले से अधिक प्रासंगिक हो जाता है। उनका संदेश यह नहीं है कि सभी लोग घर छोड़कर संन्यासी बन जाएं, बल्कि यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ मात्रा में त्याग, संतोष, संयम और सेवा को स्थान दे। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले, क्रोध पर नियंत्रण रखे, ईमानदारी से जीवन जीए और ईश्वर की भक्ति तथा मानव सेवा को महत्व दे, तो उसका जीवन भी शांत, संतुलित और आनंदमय बन सकता है।

वास्तव में संन्यासी का महानतम योगदान उसके शब्द नहीं, बल्कि उसका जीवन होता है। वह अपने आचरण से यह सिद्ध करता है कि त्याग कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। इच्छाओं का अंत ही वास्तविक स्वतंत्रता है और ईश्वर की भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च आनंद है। जब समाज ऐसे आदर्शों को अपनाता है, तब केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरा समाज नैतिकता, करुणा और आध्यात्मिकता की दिशा में आगे बढ़ता है।

सब बराबर हैं लिखने वाले के पास खुद थे सैकड़ों गुलाम! जानिए क्या है Declaration of Independence का विवाद

अगर आप हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, तो आपको लगेगा कि अमेरिका का आज़ादी का घोषणापत्र कोई ऐतिहासिक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि चोरी करने का कोई बहुत बड़ा 'खजाना' है! साल 2004 की मशहूर फिल्म नेशनल ट्रेज़र में जब हीरो निकोलस केज कहता है कि मैं इस दस्तावेज़ को चुराने वाला हूँ तो लोग रोमांच से भर गए थे। फिल्म में दिखाया गया कि इस कागज़ के पीछे छिपे हुए नक्शे, खुफिया कोड और गायब होने वाली स्याही का राज़ छुपा है। इस फिल्म ने हमारे दिमाग में इस दस्तावेज़ को किसी जादुई खजाने जैसा सेट कर दिया। लेकिन फिल्मों की दुनिया काल्पनिक होती है और हकीकत कुछ और। इस हफ्ते 4 जुलाई 2026 को अमेरिका अपनी आज़ादी के 250 साल पूरे कर रहा है। और सच बात तो ये है कि इस दस्तावेज़ के बनने की असली कहानी, हॉलीवुड के किसी भी फिल्मी ड्रामे से सौ गुना ज़्यादा दिलचस्प और रोमांचक है। वॉशिंगटन डीसी में नेशनल आर्काइव्ज़ में रखे चर्मपत्र के पिछले हिस्से पर खजाने का कोई नक्शा नहीं है। लेकिन इसके सामने के हिस्से पर कुछ ऐसे विचार लिखे हैं, जिन्होंने आधुनिक लोकतंत्र के लिए आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट और अमेरिका की सबसे लंबे समय से चल रही सांस्कृतिक लड़ाई के मुख्य केंद्र, दोनों का काम किया है। यह समझने के लिए कि आज़ादी की घोषणा पर इतना विवाद क्यों है, सबसे पहले 1776 से जुड़ी कहानियों और धारणाओं को अलग करके इसे व्यावहारिक और कठोर राजनीतिक नज़रिए से देखना होगा। 1776 की गर्मियों तक, तेरह कॉलोनियों (बस्तियों) और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक साल से ज़्यादा समय से हथियारों वाला खूनी संघर्ष चल रहा था। लेक्सिंगटन, कॉनकॉर्ड और बंकर हिल की लड़ाइयाँ पहले ही हो चुकी थीं, और जॉर्ज वॉशिंगटन की कॉन्टिनेंटल आर्मी सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से लगी हुई थी। फिर भी, युद्ध का औपचारिक राजनीतिक मकसद साफ़ नहीं था। फिलाडेल्फिया की भीषण गर्मी में मिल रही 'सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस' के कई सदस्य अभी भी ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के साथ सुलह की उम्मीद लगाए हुए थे। लंबे समय तक चले युद्ध की हकीकत सामने आने पर यह अनिश्चितता खत्म हो गई। कॉलोनियों को विदेशी मदद की सख्त ज़रूरत थी। खासकर फ्रांस और स्पेन से सैन्य और आर्थिक मदद की। हालाँकि, कैथोलिक निरंकुश राजतंत्र किसी औपनिवेशिक विद्रोह को आर्थिक मदद देने में बहुत हिचकिचाते थे, अगर वह विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर टैक्स नीति को लेकर केवल एक घरेलू झगड़ा भर होता। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए, उपनिवेशों को खुद को एक संप्रभु और अलग भू-राजनीतिक इकाई घोषित करना पड़ा। उन्हें कानूनी तौर पर साम्राज्य के बंधनों को तोड़ना ज़रूरी था। हालांकि, कैथोलिक निरंकुश राजशाही वाले देश किसी औपनिवेशिक विद्रोह को फ़ंड देने में बहुत हिचकिचाते थे, अगर वह विद्रोह सिर्फ़ ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर टैक्स पॉलिसी को लेकर कोई घरेलू झगड़ा होता। अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए, कॉलोनियों को खुद को एक संप्रभु और अलग भू-राजनीतिक इकाई घोषित करना था। उन्हें कानूनी तौर पर साम्राज्य के बंधनों को तोड़ना था।

जून 1776 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने अलग होने के औपचारिक बयान का मसौदा तैयार करने के लिए पाँच लोगों की एक समिति नियुक्त की। इस समिति में मैसाचुसेट्स के जॉन एडम्स, पेंसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन, वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन, न्यूयॉर्क के रॉबर्ट आर. लिविंगस्टन और कनेक्टिकट के रोजर शेरमन जैसे बड़े राजनीतिक नेता शामिल थे। असल में मसौदा लिखने का काम उनमें से सबसे कम उम्र के व्यक्ति को सौंपा गया: वर्जीनिया के 33 वर्षीय वकील और बागान मालिक, थॉमस जेफरसन। फिलाडेल्फिया में एक राजमिस्त्री के घर की दूसरी मंज़िल पर किराए के कमरे में काम करते हुए, जेफरसन ने लगभग सत्रह दिनों में यह मसौदा तैयार किया। उन्होंने जो लिखा, वह कोई कामकाज का संविधान या कानूनी कानून नहीं था, बल्कि एक शानदार घोषणापत्र था।

5 आसान हिस्सों में बांट कर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को समझें

1. एंट्रो: इसमें कहा गया है कि जब कोई सरकार जनता पर जुल्म करने लगे, तो कुदरत और भगवान के नियमों के अनुसार उस गुलाम देश की जनता को आज़ाद होने का पूरा हक है।
2. प्रीएंबल: यह इस दस्तावेज़ का सबसे मशहूर हिस्सा है। इसमें साफ़ कहा गया है कि सभी इंसान बराबर हैं और उन्हें जीने व आज़ाद रहने का हक है। सरकार का काम जनता की सेवा करना है, और सरकार तभी तक चलनी चाहिए जब तक जनता चाहे।
3. राजा जॉर्ज पर आरोप: इसमें ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के खिलाफ 27 बड़ी शिकायतें लिखी गई हैं। जैसे— जनता की मर्जी के बिना उन पर भारी टैक्स लगाना, जबरन अमेरिकी लोगों के घरों में ब्रिटिश सैनिकों को ठहराना और यहाँ की पंचायतों/विधानसभाओं को भंग कर देना।
4. ब्रिटिश जनता से नाराजगी: इसमें अमेरिकी लोगों ने दुख जताया है कि जब उन्होंने ब्रिटेन की आम जनता (जिन्हें वे अपना भाई मानते थे) से मदद और न्याय की गुहार लगाई, तो वहाँ के लोगों ने भी उनकी एक न सुनी।
5. आखिरी फैसला: यह अंतिम और कानूनी घोषणा है, जिसमें साफ कह दिया गया कि अब से अमेरिका के सभी राज्य पूरी तरह से आज़ाद और स्वतंत्र हैं। आखिर में आंदोलन के सभी नेताओं ने देश के लिए अपनी जान, दौलत और सम्मान की बाजी लगाने की कसम खाई।

2 जुलाई, 1776 को कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने सर्वसम्मति से आज़ादी के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। दो दिन बाद, 4 जुलाई यानी वो तारीख़ जिसे अब अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते हैं। इसी दिन घोषणापत्र का अंतिम, संशोधित रूप औपचारिक रूप से अपनाया गया।

अभियान

वर्षा से विरक्ति तक: आषाढ़ मास का गूढ़ रहस्य और जीवन को भीतर से बदलने की भारतीय परंपरा

भारतीय कालगणना में प्रत्येक मास केवल समय का एक खंड नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और उसे अधिक संतुलित, सार्थक तथा आध्यात्मिक बनाने का एक अवसर है। ऋषि-मुनियों ने प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन को मनुष्य के जीवन से जोड़कर देखा और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में ऋतुओं तथा महीनों का महत्व केवल मौसम तक सीमित नहीं रहा। इन्हीं महीनों में आषाढ़ का स्थान अत्यंत विशिष्ट माना गया है। सामान्य दृष्टि से यह वर्षा ऋतु के आरंभ का महीना है, लेकिन भारतीय दर्शन में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह ऐसा काल है, जब प्रकृति और मानव दोनों को ठहरकर स्वयं को नया बनाने का अवसर मिलता है। आषाढ़ का प्रत्येक दिन यह संदेश देता है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की होती है।

जब ग्रीष्म ऋतु की तपन अपने चरम पर पहुंच जाती है और धरती का कण-कण वर्षा की प्रतीक्षा करने लगता है, तभी आषाढ़ का आगमन होता है। पहली वर्षा की बूंद केवल मिट्टी को ही नहीं भिगोती, बल्कि मनुष्य के भीतर भी एक नई अनुभूति जगाती है। सूखे हुए पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं, खेतों में हरियाली लौट आती है, सूखी नदियां फिर से बहने लगती हैं और वातावरण में जीवन का नया संगीत गूंज उठता है। भारतीय मनीषियों ने इस परिवर्तन को केवल प्राकृतिक घटना नहीं माना, बल्कि इसे आत्मिक जागरण का प्रतीक बताया। उनका मानना था कि जिस प्रकार वर्षा धरती की थकान दूर करती है, उसी प्रकार आत्मचिंतन और साधना मनुष्य के मन पर जमी हुई नकारात्मकता को धोकर उसे नई ऊर्जा प्रदान करती है। आषाढ़ हमें यह समझाता है कि जीवन में निरंतर गति जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक समय-समय पर ठहरना भी है। आधुनिक जीवन में मनुष्य सुबह से रात तक भागदौड़ में लगा रहता है। उसके पास काम के लिए समय है, प्रतियोगिता के लिए समय है, मनोरंजन के लिए समय है, लेकिन स्वयं को समझने के लिए समय नहीं है। यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ने के बावजूद मानसिक तनाव, अकेलापन और असंतोष भी लगातार बढ़ रहे हैं। आषाढ़ का संदेश है कि यदि मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुनना चाहता है, तो उसे कुछ समय मौन, ध्यान और आत्मसंवाद के लिए अवश्य निकालना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, उसके लिए जीवन की अनेक उलझनें स्वतः सरल हो जाती हैं। भारतीय ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले ही यह अनुभव कर लिया था कि वर्षा ऋतु आत्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इसी कारण पूरे वर्ष समाज के बीच भ्रमण करने वाले संत और मुनि आषाढ़ के आगमन के साथ एक स्थान पर निवास करने लगते थे। वे यात्राएं रोककर अपने आश्रमों में वेद, उपनिषद, योग, आयुर्वेद, दर्शन और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर चिंतन करते थे। उनके शिष्य भी इसी अवधि में गंभीर अध्ययन और साधना में लीन रहते थे। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं थी, बल्कि पर्यावरण और जीव संरक्षण की भावना से भी जुड़ी हुई थी। वर्षा ऋतु में असंख्य छोटे-छोटे जीव-जंतु जन्म लेते हैं। अनावश्यक यात्राओं से उनके जीवन को हानि पहुंच सकती थी। इसलिए ऋषियों ने प्रकृति के सूक्ष्मतम जीवन के प्रति भी संवेदनशीलता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। आषाढ़ का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि परिवर्तन हमेशा भीतर से आरंभ होता है। संसार को बदलने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति यदि स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करता, तो उसका प्रयास अधूरा रह जाता है। वर्षा के समय किसान पहले भूमि तैयार करता है, फिर बीज बोता है और उसके बाद धैर्यपूर्वक फसल की प्रतीक्षा करता है। यही सिद्धांत मानव जीवन पर भी लागू होता है। यदि मनुष्य अपने भीतर अच्छे विचारों, श्रेष्ठ संस्कारों और सकारात्मक दृष्टिकोण के बीज नहीं बोएगा, तो जीवन में सुख और सफलता की फसल कैसे प्राप्त होगी? आषाढ़ हमें अपने मन की भूमि को तैयार करने का अवसर देता है।

यह महीना भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनेक महत्वपूर्ण पर्वों का आधार भी है। योगिनी एकादशी मन और आत्मा की शुद्धि का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि केवल शरीर की सफाई पर्याप्त नहीं, बल्कि विचारों की पवित्रता भी आवश्यक है। भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा समाज में समानता और समरसता की भावना को मजबूत करती है। यह बताती है कि ईश्वर किसी विशेष वर्ग के नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव समाज के हैं। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का शुभारंभ होता है, जो जप, तप, दान, स्वाध्याय और आत्मसंयम का विशेष काल माना गया है। इसी आध्यात्मिक वातावरण में गुरु पूर्णिमा आती है, जो गुरु के प्रति कृतज्ञता, ज्ञान के सम्मान और विनम्रता का महान पर्व है। इस प्रकार आषाढ़ का प्रत्येक उत्सव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संदेश देता है। आषाढ़ का प्रकृति से संबंध अत्यंत गहरा है। वर्षा के साथ जलाशय भरते हैं, खेतों में बुआई आरंभ होती है, पशु-पक्षियों में नई स्फूर्ति दिखाई देती है और समूचा वातावरण जीवनदायी बन जाता है। भारतीय संस्कृति ने इस समय को वृक्षारोपण और जल संरक्षण का सबसे उपयुक्त अवसर माना है। आज पूरी दुनिया जल संकट, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे समय में आषाढ़ का संदेश अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्षा जल का संरक्षण करे, पौधे लगाए और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है।

आयुर्वेद भी आषाढ़ मास को स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। वर्षा ऋतु में पाचन शक्ति अपेक्षाकृत कमजोर हो जाती है। इसलिए हल्का, सात्विक और ताजा भोजन करने की सलाह दी जाती है। उपवास, संयमित आहार और नियमित दिनचर्या शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। भारतीय परंपरा में धार्मिक नियमों के पीछे स्वास्थ्य विज्ञान का भी गहरा आधार रहा है। उपवास केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि शरीर को विश्राम देने और पाचन तंत्र को संतुलित रखने का एक वैज्ञानिक उपाय भी है। आषाढ़ मानसिक संतुलन का भी महीना है। आज का मनुष्य सूचना और तकनीक के महासागर में घिरा हुआ है। दिनभर मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े रहने के कारण मन को विश्राम नहीं मिल पाता। ऐसे समय में प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना, वर्षा की बूंदों का आनंद लेना, ध्यान करना, योग करना और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि ध्यान और प्रकृति के संपर्क से तनाव कम होता है तथा सकारात्मक सोच विकसित होती है। यह महीना हमें संयम का महत्व भी सिखाता है। वर्षा तभी लाभदायक होती है जब वह संतुलित मात्रा में हो। अत्यधिक वर्षा बाढ़ लाती है और बहुत कम वर्षा सूखा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। अत्यधिक इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं, जबकि इच्छाओं का पूर्ण अभाव जीवन की प्रेरणा को कम कर सकता है। इसलिए भारतीय दर्शन ने मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी है। आषाढ़ का संदेश यही है कि जीवन में संतुलन ही स्थायी सुख का आधार है।

आधुनिक समाज में आध्यात्मिकता को अक्सर केवल पूजा-पाठ तक सीमित समझ लिया जाता है, जबकि भारतीय परंपरा आध्यात्मिकता को जीवन जीने की कला मानती है। सत्य बोलना, ईमानदारी से कार्य करना, दूसरों की सहायता करना, माता-पिता और गुरु का सम्मान करना, प्रकृति का संरक्षण करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना—ये सभी आध्यात्मिक जीवन के अंग हैं। आषाढ़ हमें इन्हीं मूल्यों को व्यवहार में उतारने की प्रेरणा देता है। इस महीने का सबसे बड़ा संदेश संकल्प है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। यदि कोई व्यक्ति आषाढ़ में यह संकल्प ले कि वह प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करेगा, किसी एक बुरी आदत का त्याग करेगा, जल की बर्बादी नहीं करेगा, हर सप्ताह एक सेवा कार्य करेगा या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएगा, तो यह छोटा प्रयास उसके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। संकल्प ही साधना का पहला चरण है और साधना ही सफलता की वास्तविक आधारशिला है। आषाढ़ यह भी सिखाता है कि जीवन का विकास केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं होता। धन, पद और प्रतिष्ठा आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन यदि मन अशांत है, संबंध कमजोर हैं और जीवन में संतोष नहीं है, तो सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, “Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

छोटाउदेपुर के राजवासणा में हेरण नदी पर 82 करोड़ रुपए से अधिक तथा तापी में अंबिका नदी पर 79 करोड़ रुपए से अधिक के खर्च से आकार ले रहे हैं दो आधुनिक रबर डैम

गुजरात में पहली बार दक्षिण कोरियाई तकनीक और जापानी डिजाइन से बनेंगे दो 'एयर-फील्ड रबर डैम'

राजवासणा रबर डैम

- छोटाउदेपुर के 'राजवासणा रबर डैम से 25 गांवों के 3420 हेक्टेयर क्षेत्र को होगा सीधा लाभ'
- 3.5 एमसीएम पानी के संग्रह के साथ हेरण नदी की बाढ़ और गाद की समस्या का निकलेगा स्थायी समाधान
- बोडेली के राजवासणा में हेरण नदी पर 30 महीने में साकार होगा अत्याधुनिक रबर डैम
- फिलहाल डैम का 75 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है

पाठकवाड़ी रबर डैम

- जापानी डिजाइन पर आधारित अत्याधुनिक 'रबर डैम' से 650 हेक्टेयर भूमि को मिलेगा सिंचाई का पानी
- यह रबर ब्लैडर 50 डिग्री से अधिक तापमान सहने के लिए डिजाइन किया गया है, इसकी अनुमानित उम्र लगभग 30 वर्ष है
- अब तक डैम का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है

गांधीनगर, 06 जून : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'कैच द रेन' अभियान के और गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक सिंचाई और पानी की सुविधा को सुदृढ़ करन के लक्ष्य के साथ अनेक भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत, छोटाउदेपुर जिले की बोडेली तहसील के राजवासणा गांव के निकट हेरण नदी पर अत्याधुनिक 'राजवासणा रबर डैम' तथा तापी जिले की डोलवण तहसील के पाठकवाड़ी गांव में अंबिका नदी पर 'पाठकवाड़ी रबर डैम' सहित कुल दो आधुनिक रबर डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिनका कार्य अभी प्रगति पर है। इन डैमों के निर्माण में जापानी डिजाइन और दक्षिण कोरियाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।

जल संसाधन और जलापूर्ति मंत्री श्री ईश्वरसिंह पटेल के मार्गदर्शन में राजवासणा में 82.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस अनोखे रबर डैम को अगले 30 महीनों यानी सितंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस डैम के तैयार होने से आसपास के 25 गांवों के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, तापी की अंबिका नदी पर पाठकवाड़ी गांव में 79 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जापानी डिजाइन पर आधारित अत्याधुनिक 'रबर डैम' तैयार किया जा रहा है। इस डैम के तैयार होने से लगभग 650 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी का मिलेगा, जिसका सीधा फायदा स्थानीय किसानों को होगा।

राजवासणा रबर डैम की विशेषता

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हेरण नदी पर 180 मीटर की लंबाई और 3.5 मीटर की ऊंचाई वाला एक आधुनिक रबर ब्लैडर स्थापित किया जाएगा। इस रबर डैम टेक्नोलॉजी की मुख्य विशेषता यह है कि इससे मौजूदा पुराने वीयर (छोटे बांध) की जल संग्रह क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और कुल 3.5 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी का भंडारण किया जा सकेगा। इसके चलते, आसपास के क्षेत्रों का भूमिगत जल स्तर काफी ऊंचा उठ जाएगा, जिससे सिंचाई और पेयजल का पानी आसानी से उपलब्ध होगा। मौजूदा स्थिति के अनुसार डैम का 75 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

अन्य फायदे

गाद से मुक्ति :
पुराने वीयर में जमा होने वाली रेत और गाद के कारण जल भंडारण क्षमता कम हो जाती थी, अब रबर डैम पद्धति से इस गाद को पूरी तरह से हटाया जा सकेगा।
बाढ़ नियंत्रण : मानसून के दौरान भारी बाढ़ की स्थिति में रबर डैम को 'डिफ्लेट' (हवा निकालकर खाली करना) किया जा सकेगा, जिससे बाढ़ का पानी तेजी से निकलने से आसपास के गांवों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। नदी के बाएं तट पर 900 मीटर और दाएं तट पर 500 मीटर लंबी फ्लड प्रोटेक्शन वॉल (सुरक्षा दीवार) भी बनाई जाएगी।

10 वर्ष तक संचालन और रखरखाव :

इस कॉन्ट्रैक्ट में अगले 10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव (ओएंडएम) शामिल है। इससे लगातार तकनीकी सुविधा मिलती रहेगी और डैम सही ढंग से कार्यरत रहेगा।

25 गांवों के 3420 हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेगी संजीवनी

इस डैम के निर्माण से वीयर-आधारित नहरों के माध्यम से क्षेत्र के किसानों को रबी (शीतकालीन) और खरीफ (मानसून) के सीजन में खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल पाएगा। इतना ही नहीं, भविष्य में राजवासणा वीयर योजना की नहरों को आसपास के 25 लाभार्थी गांवों के तालाबों से जोड़ दिया जाएगा। इस अतिरिक्त पानी से गांव के तालाबों को भरने से इस पूरे क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई के पानी की समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी।

पाठकवाड़ी रबर डैम के बारे में

प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और बारहमासी नदियों वाले दक्षिण गुजरात के तापी जिले में जल संचय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और आधुनिक क्रांति होने जा रही है। तापी जीले की सुदूरवर्ती डोलवण तहसील के पाठकवाड़ी गांव के निकट से गुजरने वाली अंबिका नदी पर सरकार ने 79.13 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक 'एयर-फील्ड रबर डैम' (पानी रोकने के लिए हवा से भरी हुई रबर की बॉडी या ट्यूब) बनाने का काम शुरू किया गया है। इस योजना के साकार होने पर पाठकवाड़ी सहित ढोडियावाड़, उनाई और सिंधई जैसे गांवों के किसानों को खरीफ और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए पर्याप्त पानी सुलभ होगा। वर्तमान में इस डैम का 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

भौगोलिक चुनौतियों से निपटने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट उपाय

तापी जिले का यह इलाका समतल होने के कारण और नदी के दोनों तट ढलान वाले होने के कारण यहां पारंपरिक रूप से ऊंचाई वाले चेकडैम या वीयर संरचना का निर्माण संभव नहीं था। स्थानीय किसान अग्रणियों और विधायक श्री मोहनभाई कोंकणी के निवेदन के चलते विभाग ने इस बारे में सर्वेक्षण किया। जिसके आधार पर पारंपरिक बैराज के स्थान पर अधिक जल संग्रहण की क्षमता वाला जापानी टेक्नोलॉजी पर आधारित 'एयर-फील्ड रबर डैम' बनाने का अभिनव निर्णय लिया गया।

जापानी डिजाइन और कोरियन रबर ब्लैडर की विशेषता

इस अनोखे डैम को जापानी कोड 2000 के अनुसार डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला विशेष प्रकार का रबर ब्लैडर दक्षिण कोरिया से मंगाया गया है, जिसकी चौड़ाई 18 एमएम से 32 एमएम तक है। यह रबर ब्लैडर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को सहन करते हुए उत्तम तरीके से काम करने में सक्षम है। इसकी अनुमानित उम्र 30 वर्ष है।

एससीएडीए ऑटोमेशन से होगा संचालन

इस डैम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें बिना किसी मैनपावर के कंप्यूटर के जरिए सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन (एससीएडीए) ऑटोमेशन सिस्टम से ही रबर ब्लैडर में हवा भरने (इन्फ्लेट) और हवा निकालने (डिफ्लेट) का काम आसानी से हो पाएगा। 2.50 मीटर के रबर ब्लैडर को 'जे' बोल्ट (अंग्रेजी के 'जे' अक्षर के आकार वाला) से 2.00 मीटर के कंक्रीट बेस पर फिक्स किया जाएगा। इससे डैम की कुल ऊंचाई 4.50 मीटर और कुल लंबाई 280 मीटर (4 स्पैन) सुनिश्चित होगी।

मानसून में बाढ़ और मिट्टी का कटाव रुकेगा

पारंपरिक स्टील गेटेड डैम की तुलना में रबर डैम मानसून में बाढ़ के दौरान नदी के प्रवाह में जरा भी अवरोध पैदा नहीं करता, जिससे नदी तट की मिट्टी का कटान रुकेगा। इसके अलावा, रबर की हवा निकालने पर नदी के बहाव के साथ आने वाली गाद भी आसानी से बह जाएगी, जिससे डैम की जल संग्रहण क्षमता वर्षों तक बनी रहेगी।

650 हेक्टेयर जमीन को मिलेगी संजीवनी और भूमिगत जल स्तर में वृद्धि

इस आधुनिक रबर डैम के बनने से लगभग 3.50 लाख घन मीटर (3.50 एमसीएम) विशाल जलराशि का संग्रहण होगा, जिसके सीधे फायदे के रूप में आसपास की 650 हेक्टेयर जमीन के लिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी। इतना ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के कुएं और बोर का भूमिगत जल स्तर ऊंचा उठने से स्थानीय लोगों को पेयजल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। भविष्य में यह टेक्नोलॉजी समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में मिलने से रोकने के लिए 'टाइडल रेगुलेटर' के रूप में भी अत्यंत उपयोगी साबित होगी।

मुंबई सेंट्रल मंडल में जलभराव के कारण रेल यातायात प्रभावित

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में भारी वर्षा के कारण सफाले, केलवे रोड, वसई रोड एवं नालासोपारा स्टेशनों के बीच जलभराव होने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। प्रभावित ट्रेनों विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक निरस्त ट्रेनें

ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को वलसाड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–अहमदाबाद कर्णावती एक्सप्रेस 06.07.2026 को वलसाड स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

- ट्रेन संख्या 12479 जोधपुर–बांद्रा टर्मिनस सूर्यनगरी एक्सप्रेस दिनांक (यात्रा प्रारंभः 05.07.2026) को वापी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12480 बांद्रा टर्मिनस–जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को वापी शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।
- ट्रेन संख्या 12932 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को सूरत स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12931 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को सूरत से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।
- ट्रेन संख्या 12990 अजमेर–दादर एक्सप्रेस दिनांक 05.07.2026 को (यात्रा प्रारम्भ करने वाली) नवसारी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 12989 दादर–अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 06.07.2026 को नवसारी से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।
- ट्रेन संख्या 22962 अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को दिनांक 06.07.2026 को वापी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 22961 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस वापी से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।
- ट्रेन संख्या 82902 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस को दिनांक 06.07.2026 को बिलीमोरा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 82902 -अहमदाबाद- मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस बिलिमोरा से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।
- ट्रेन संख्या 20908 भुज–दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस को दिनांक 05.07.2026 को (यात्रा प्रारम्भ करने वाली) सूरत स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा ट्रेन संख्या 20907 दादर-भुज एक्सप्रेस सूरत से शॉर्ट ओरिजिनेट (प्रारम्भ) होगी।

रेगुलेट ट्रेनें

- 12932 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल डबल डेकर एक्सप्रेस – गोठनगाम
- 82902 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस – किम
- 20908 भुज – दादर सयाजी नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस – अंकलेश्वर
- 22954 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस – लाकोदरा देथान
- 16588 बीकानेर – यशवंतपुर एक्सप्रेस – इटोला
- 22738 हिसार – सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस – बाजवा
- 19016 पोरबंदर – दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस – वासद

मध्य रेल में भूस्खलन के कारण कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया हैः

मार्ग परिवर्तित ट्रेनें

- ट्रेन संख्या 22920 अहमदाबाद–चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 06.07.2026) को सूरत–पालधी–जलगांव–मनमाड–दौंड के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 11092 पुणे–भुज एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 06.07.2026) को दौंड–मनमाड–जलगांव–पालधी–सूरत के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 12298 पुणे–अहमदाबाद दुरंतो एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 06.07.2026) को दौंड कॉर्ड–मनमाड–इगतपुरी–कल्याण के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 09420 तिरुचिरापल्ली–अहमदाबाद स्पेशल (यात्रा प्रारंभः 05.07.2026) को दौंड–मनमाड–जलगांव–पालधी–सूरत के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 20953 चेन्नई सेंट्रल–अहमदाबाद एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 05.07.2026) को दौंड–मनमाड–जलगांव–पालधी–सूरत के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 22717 राजकोट-सिकंदराबाद एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 06.07.2026) को सूरत–पालधी–जलगांव–मनमाड–दौंड के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 16531 अजमेर-केएसआर बेंगलुरु एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 06.07.2026) को सूरत–पालधी–जलगांव–मनमाड–दौंड के रास्ते चलेगी।
- ट्रेन संख्या 20495 जोधपुर-हड़पसर एक्सप्रेस (यात्रा प्रारंभः 05.07.2026) को सूरत–पालधी–जलगांव–मनमाड–दौंड के रास्ते चलेगी।

गुजरात में रिहायशी इलाके तक पहुंचा शेर, किसान पर जानलेवा हमला; आधे घंटे तक जबड़ों में दबाए रखा हाथ, संघर्ष कर बचाई जान

भावनगर। गुजरात के भावनगर जिले के पालीताना तालुका में सोमवार सुबह हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। गरजिया गांव में एक एशियाई शेर ने खेत की ओर जा रहे किसान पर हमला कर दिया और उसका हाथ अपने जबड़ों में दबोचकर करीब आधे घंटे तक पकड़े रखा। किसान ने दर्द और भय के बीच अद्भुत साहस का परिचय देते हुए लगातार संघर्ष किया और अंततः किसी तरह खुद को शेर के चंगुल से छुड़ाने में सफल रहा। गंभीर रूप से घायल किसान को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल है। वन विभाग ने सूचना मिलते ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है और शेर को सुरक्षित पकड़ने के लिए इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। घायल किसान की पहचान कालूभाई बोगभाई परमार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह वह रोज की तरह अपनी गाय को चारा खिलाने के लिए घर से निकले थे। गांव से कुछ दूरी पर पहुंचते ही झाड़ियों की ओर से अचानक एक शेर निकला और बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। कालूभाई के अनुसार, शेर ने सबसे पहले उनकी पीठ पर जोरदार वार किया, जिससे वह संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद शेर ने उनके हाथ को अपने शक्तिशाली जबड़ों में दबोच लिया। अचानक हुए इस हमले से वह पूरी तरह असहाय हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कालूभाई ने बताया कि शेर लंबे समय तक उनका हाथ नहीं छोड़ रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन उन्होंने लगातार खुद को

बचाने की कोशिश जारी रखी। उन्होंने शेर के चेहरे और शरीर पर हाथों से वार करना और उसे खरोंचना शुरू किया। काफी देर तक चले इस संघर्ष के बाद शेर की पकड़ कुछ ढीली हुई। इसी मौके का फायदा उठाकर उन्होंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागने लगे। किसान के भागते ही शेर का ध्यान पास में बंधी उनकी गाय की ओर चला गया, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने का मौका मिल गया।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किसान लंबे समय तक शेर से संघर्ष करता रहा और उसके साहस के कारण ही उसकी जान बच सकी। घायल अवस्था में उसे गांव के लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार किसान के हाथ और शरीर पर गहरे घाव आए हैं, हालांकि उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इसी शेर ने कुछ समय पहले गांव के एक अन्य निवासी हेमूभाई गढ़वी को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की थी। हेमूभाई ने बताया कि सुबह करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच शेर उनके घर के पास बनी बाड़ में घुस आया था। उस समय वह अपनी भैंस को बाहर निकाल रहे थे। जैसे ही शेर ने उन्हें देखा, वह तेजी से उनकी ओर दौड़ा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हेमूभाई तुरंत भागे और पास में रहने वाले अपने भाई के घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। इस दौरान उनकी भैंस घबराकर गिर गई, जिससे शेर का ध्यान उनकी ओर से हट गया और उनकी जान बच गई। कुछ ही देर बाद वही शेर गांव के दूसरे हिस्से में पहुंचा और कालूभाई परमार पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गरजिया गांव के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना है कि शेर के आबादी वाले इलाके में घूमने की खबर पहले भी कई बार दी गई थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। गांव के सरपंच के पति सावजीभाई ने बताया कि सूचना देने के लगभग डेढ़ घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद अधिकारियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर शेर को सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। वन विभाग के कर्मचारी लगातार आसपास के खेतों, झाड़ियों और जंगल से लगे इलाकों में निगरानी कर रहे हैं ताकि शेर को बिना किसी नुकसान के पकड़ा जा सके और उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा सके। घटना के बाद गरजिया गांव सहित आसपास के कई गांवों में भय का माहौल है। ग्रामीण अपने घरों से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं। किसान खेतों में अकेले जाने से बच रहे हैं और पशुपालकों ने भी अपने मवेशियों को खुले में छोड़ने के बजाय सुरक्षित स्थानों पर बांधना शुरू कर दिया है। सबसे अधिक चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। डर के कारण सोमवार को कई बच्चों ने स्कूल नहीं जाने का फैसला किया और अभिभावकों ने भी उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। गांव में दिनभर लोग समूह बनाकर ही आवागमन करते रहे।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से वन्यजीवों की आबादी बढ़ने और जंगलों के आसपास मानवीय गतिविधियां बढ़ने के कारण शेरों का रिहायशी क्षेत्रों की ओर आना लगातार बढ़ रहा है। इससे इंसानों और वन्यजीवों के बीच टकराव की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों का मानना है कि यदि समय रहते निगरानी और बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

पालीताना तालुका पंचायत सदस्य चेतन डाभी ने भी घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए वन विभाग से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आबादी वाले क्षेत्रों में घूम रहे शेरों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा जाना चाहिए ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों ने पहले भी कई बार वन विभाग को शेरों की गतिविधियों की जानकारी दी थी, लेकिन शिकायतों पर समय रहते पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि पहले सतर्कता बरती जाती तो इस तरह की गंभीर घटना टाली जा सकती थी।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टीम लगातार इलाके में निगरानी कर रही है और शेर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे अकेले खेतों या जंगल से सटे क्षेत्रों में न जाएं, बच्चों को बिना निगरानी के बाहर न भेजें और किसी भी वन्यजीव की मौजूदगी की सूचना तुरंत विभाग को दें। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है।

यह घटना एक बार फिर मानव और वन्यजीव संघर्ष के बढ़ते खतरे को सामने लेकर आई है। एक ओर गुजरात के एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि संरक्षण की सफलता मानी जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकलकर आबादी वाले क्षेत्रों में पहुंचने की घटनाएं प्रशासन और वन विभाग के लिए नई चुनौती बनती जा रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति, बेहतर निगरानी व्यवस्था और स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

अहमदाबाद मंडल: डीआरएम वेद प्रकाश ने किया मानसून तैयारियों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों का सघन निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर मानसून के दौरान सुचारू रेल परिचालन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मण्डल रेल प्रबंधक (DRM) श्री वेद प्रकाश ने 05.07.2026 को अहमदाबाद-बारेजड़ी और अहमदाबाद-विरमगाम रेलखंडों का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मानसून की तैयारियों, जल निकासी व्यवस्था और मण्डल पर विभिन्न स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास कार्य की समीक्षा की।

मानसून तैयारी एवं सुरक्षा पर विशेष ध्यान

निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक ने वर्षा के दौरान ट्रैक पर जलभराव (Waterlogging) को रोकने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रेल पटरियों के किनारे स्थित नालों और पुलों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि पानी का बहाव निर्बाध रहे। साथ ही, रेल अंडर ब्रिज (RUBs) का भी निरीक्षण किया गया ताकि बारिश में जल जमाव के कारण यातायात बाधित न हो।

निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा

मंडल में यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षमता वृद्धि के लिए चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए डीआरएम ने अहमदाबाद-कांकरिया और वटवा के बीच निर्माणाधीन चौथी लाइन (4th Line) के कार्य का अवलोकन किया। यह चौथी लाइन भविष्य में अहमदाबाद जंक्शन पर रेल यातायात के दबाव को कम करने और ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

स्टेशनों एवं कॉलोनियों में स्वच्छता का निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने विरमगाम स्टेशन, रेलवे कॉलोनी, जखवाड़ा स्टेशन और अहमदाबाद स्टेशन का सघन दौरा किया। उन्होंने स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का फीडबैक लिया और स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने पर जोर दिया।

स्वच्छता का विशेष अभियानः डीआरएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रेलवे स्टेशनों के साथ-साथ रेलवे कॉलोनियों में भी स्वच्छता अभियान (Cleanliness Drive) को एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में चलाया जाए।

अपशिष्ट प्रबंधनः स्टेशनों पर कचरा निपटान (Waste Disposal) की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य एवं सफाई निरीक्षकों को प्रभावी कदम उठाने के आदेश दिए।

इस निरीक्षण के दौरान मंडल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मण्डल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फील्ड स्टाफ पूरी तरह सतर्क और तैयार रहे।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

गुजरात विधानसभा पोडियम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र के समक्ष भावपुष्प अर्पित कर कृतज्ञता व्यक्त की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रखर राष्ट्रवादी विचारक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात विधानसभा पोडियम में श्यामा प्रसाद जी के तैल चित्र के समक्ष भावपुष्प अर्पित किए।

मुख्यमंत्री ने डॉ. मुखर्जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और सामान्य नागरिक अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया था।

उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान की नीति को दूर करने का डॉ. मुखर्जी का विजन आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में साकार हुआ है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि डॉ. मुखर्जी के विचार और राष्ट्र प्रथम की भावना सभी के हृदय में मातृभूमि

के प्रति समर्पण की ज्योति को सदैव प्रज्वलित रखेगी।

इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री पूर्णेशभाई मोदी, सचेतक श्री बालकृष्ण शुक्ल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, श्री अल्पेशभाई ठाकोर, गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉ. आशीष दवे, उप महापौर और मनपा के पदाधिकारी तथा विधानसभा सचिव श्री चेतन पंड्या सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट; उत्तराखंड से महाराष्ट्र तक भारी बारिश का खतरा, कई राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की आशंका

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने देश के अधिकांश हिस्सों में अपनी रफ्तार तेज कर दी है और इसके साथ ही उत्तर, पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा का दौर शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र के अनेक जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार हो रही वर्षा के कारण कई स्थानों पर जलभराव, यातायात बाधित होने, नदियों के जलस्तर में वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ सकती हैं।

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार आगे बढ़ रहा है और उसकी उत्तरी सीमा इस समय जामनगर, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनू, हिसार और भटिंडा से होकर गुजर रही है। अनुकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुए अगले तीन दिनों के दौरान मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के शेष हिस्सों तक पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां और तेज होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिनभर रुक-रुक कर मध्यम से तेज बारिश, गरज-चमक और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 10 जुलाई तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे उमस से राहत मिलेगी लेकिन दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है।

उत्तर भारत में मानसून का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार वर्षा के कारण भूस्खलन, चट्टानें खिसकने और सड़क मार्ग बाधित होने की आशंका है। चारधाम यात्रा मार्गों सहित कई संवेदनशील इलाकों में प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दोनों राज्यों के अनेक जिलों में भारी वर्षा के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। निचले इलाकों में जलभराव और छोटी नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए यह वर्षा खरीफ फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है, हालांकि अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में फसलों को नुकसान की आशंका भी बनी रहेगी।

मध्य भारत में मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ओडिशा और झारखंड के कई क्षेत्रों में भी लगातार बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन राज्यों में नदियों और जलाशयों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पश्चिम भारत में गुजरात, कोंकण-गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की संभावना को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कई जिलों में शहरी बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनने की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने भी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र ओडिशा तट को पार कर चुका है और अब अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर ओडिशा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से इन क्षेत्रों में व्यापक वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अलावा यह प्रणाली उत्तर और मध्य भारत में भी मानसूनी गतिविधियों को मजबूत करेगी, जिसके कारण आने वाले दिनों में कई राज्यों में वर्षा का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून की सक्रियता के कारण हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज-चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई स्थानों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े रहने से बचने की सलाह दी गई है।

आईएमडी ने भारी बारिश वाले क्षेत्रों के लिए विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने कहा है कि लगातार वर्षा के कारण निचले इलाकों में जलभराव, शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम, सड़क और रेल यातायात में बाधा, नदी-नालों के उफान पर आने और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें, मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा बुलेटिन पर नजर रखें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

आपदा प्रबंधन एजेंसियों को भी संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट पर रखा गया है। जहां बाढ़ या भूस्खलन की आशंका अधिक है, वहां राहत एवं बचाव दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निकायों को जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त रखने, बिजली विभाग को आपूर्ति व्यवस्था पर निगरानी रखने और स्वास्थ्य विभाग को संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून का यह सक्रिय चरण कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि इससे खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलेगी और जलाशयों में जल संग्रह भी बढ़ेगा। हालांकि लगातार और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों, सड़क संपर्क और सामान्य जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में अगले कुछ दिन देश के कई हिस्सों के लिए मौसम की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं और लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।

बीज से बुने सपने: गुजरात के दो छात्रों ने 3,000 किलोमीटर की सीखने की यात्रा में कपास से तैयार किया अपना कुर्ता, अनुभव आधारित शिक्षा की बनी मिसाल

वडोदरा। ऐसे समय में जब अधिकांश बच्चों की शिक्षा किताबों, स्मार्ट क्लास और डिजिटल स्क्रीन तक सीमित होती जा रही है, गुजरात के वडोदरा स्थित ध्याना रिसर्च सिटी (ध्याना संशोधन नगरी) के दो 12 वर्षीय विद्यार्थियों ने सीखने का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसने अनुभव आधारित शिक्षा की नई मिसाल कायम कर दी है। प्रांसु और शिवा नाम के इन दोनों विद्यार्थियों ने केवल कपास का पौधा उगाना ही नहीं सीखा, बल्कि खेत में कपास के बीज बोने से लेकर फसल तैयार करने, रुई निकालने, धागा कातने, हैंडलूम पर कपड़ा बुनने और अंततः उसी कपड़े से अपने लिए पारंपरिक कुर्ते सिलने तक की पूरी प्रक्रिया स्वयं पूरी की। यह पूरी यात्रा केवल एक शैक्षणिक परियोजना नहीं रही, बल्कि आत्मनिर्भरता, श्रम के सम्मान, पारंपरिक भारतीय शिल्प, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण बन गई।

'सीड टू क्लॉथ (बीज से वस्त्र तक)' नामक इस विशेष परियोजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह समझाना था कि रोजमर्रा में पहने जाने वाले एक साधारण कपड़े के पीछे कितनी लंबी, जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है। आज के समय में जब तैयार कपड़े आसानी से बाजार में उपलब्ध हैं, तब अधिकांश बच्चों को यह जानकारी भी नहीं होती कि कपास से वस्त्र बनने तक कितने चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी सोच के साथ दोनों विद्यार्थियों ने खेती से लेकर वस्त्र निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया को स्वयं अनुभव किया।

परियोजना के तहत सबसे पहले उन्होंने कपास के बीज बोए और उनकी नियमित देखभाल की। पौधों के बढ़ने, सिंचाई, संरक्षण और फसल तैयार होने तक प्रत्येक चरण में उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। कपास तैयार होने के बाद उसकी तुड़ाई की गई और फिर रुई तैयार करने की पारंपरिक विधियों को सीखा गया। इसके बाद हाथ से धागा कातना, ताना तैयार करना और पारंपरिक हैंडलूम पर कपड़ा बुनने जैसी जटिल प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण लिया गया। अंत में इसी हाथ से बुने हुए कपड़े से दोनों विद्यार्थियों ने अपने पारंपरिक कुर्ते तैयार करवाए। इस पूरे अनुभव को उन्होंने केवल सीखने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने हाथों से बने कुर्ते पहनकर ऐतिहासिक ताजमहल का भ्रमण भी किया, जो इस परियोजना का प्रतीकात्मक और यादगार क्षण बन गया।

संस्थान के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य केवल हस्तकला सिखाना नहीं था। इसके माध्यम से बच्चों में धैर्य, अनुशासन, श्रम के प्रति सम्मान, टीमवर्क, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी जैसे जीवन मूल्यों का विकास करना भी लक्ष्य था। विद्यार्थियों ने महसूस किया कि जिस वस्त्र को लोग कुछ मिनटों में खरीद लेते हैं, उसके पीछे किसानों, कताई करने वालों, बुनकरों और दर्जियों की कितनी मेहनत, समय और कौशल जुड़ा होता है। इस अनुभव ने उन्हें श्रम के वास्तविक महत्व और भारतीय हस्तशिल्प की गरिमा को समझने का अवसर दिया।

पारंपरिक बुनाई की विभिन्न तकनीकों को गहराई से समझने के लिए दोनों विद्यार्थियों ने लगभग 3,000 किलोमीटर लंबी अध्ययन यात्रा भी की। इस यात्रा की शुरुआत गुजरात के प्रसिद्ध बुनकर गांव भुजोडी से हुई, जहां उन्होंने पारंपरिक कच्छी बुनाई की विशेषताओं को जाना। इसके बाद वे महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे, जहां खादी और पारंपरिक वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को निकट से समझा। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट स्थित मैत्री आश्रम रहा। यहां उन्होंने स्थानीय बुनकरों और कारीगरों के साथ रहकर पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध हैंडलूम परंपरा का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। स्थानीय शिल्पकारों के साथ काम करते हुए उन्होंने बुनाई की उन तकनीकों को सीखा, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और आज भी भारतीय सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

ध्याना रिसर्च सिटी का कहना है कि इस पूरी पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल तकनीकी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, स्थानीय कारीगरों और आत्मनिर्भर जीवनशैली से जोड़ना भी था। संस्थान का मानना है कि शिक्षा तभी सार्थक होती है जब विद्यार्थी पुस्तकीय ज्ञान के साथ वास्तविक जीवन के अनुभव भी प्राप्त करें। इसी सोच के तहत भविष्य में परिसर में स्थायी हैंडलूम स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इस पारंपरिक कला का प्रशिक्षण मिल सके और भारतीय बुनाई परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके।

पूरे अभियान को प्रतीकात्मक रूप से 'रूपेल्स वल्चर की तरह ऊंची उड़ान' नाम दिया गया। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल रूपेल्स वल्चर से प्रेरित इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पारंपरिक शिक्षा की सीमाओं से बाहर निकलकर व्यापक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करना था। यह संदेश भी दिया गया कि ऊंची उड़ान केवल करियर में सफलता हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन को गहराई से समझने, प्रकृति के साथ जुड़ने और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने की क्षमता विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। विशेष रूप से असम में प्रतिकूल मौसम और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने स्थानीय कारीगरों के सहयोग से लगभग 15 मीटर कपड़ा सफलतापूर्वक बुना। लगातार अभ्यास, अनुशासन और सीखने की इच्छा ने उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया। संस्थान का कहना है कि यही अनुभव बच्चों में समस्या-समाधान की क्षमता और आत्मनिर्भर सोच विकसित करने में सबसे अधिक सहायक साबित हुआ।

यह अध्ययन यात्रा केवल वस्त्र निर्माण तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनी। पश्चिम भारत से पूर्वोत्तर भारत तक की यात्रा के दौरान दोनों विद्यार्थियों ने अलग-अलग समुदायों के साथ समय बिताया, उनकी जीवनशैली, परंपराओं, भोजन, संस्कृति और कार्यपद्धति को निकट से देखा। इससे उनमें भारत की विविधता के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय एकता की भावना और अधिक मजबूत हुई। विभिन्न क्षेत्रों के कारीगरों के साथ संवाद ने यह भी सिखाया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और पारंपरिक ज्ञान में निहित है।

संस्थान का स्पष्ट मानना है कि आधुनिक शिक्षा केवल परीक्षा और अंकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। बच्चों को प्रकृति, कृषि, पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भर जीवनशैली से जोड़ना भी शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। 'सीड टू क्लॉथ' जैसी परियोजनाएं विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी, सतत विकास की समझ और व्यावहारिक कौशल विकसित करती हैं। ऐसे अनुभव बच्चों को केवल बेहतर विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनाते हैं।

प्रांसु और शिवा की यह अनूठी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यदि बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता, सही मार्गदर्शन और वास्तविक अनुभवों से जुड़ने का अवसर मिले तो वे अपेक्षा से कहीं अधिक रचनात्मक और प्रेरणादायी कार्य कर सकते हैं। उनकी यह यात्रा केवल दो विद्यार्थियों की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है कि अनुभव आधारित शिक्षा, पारंपरिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता को यदि पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए तो आने वाली पीढ़ी केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक कौशल से संपन्न, प्रकृति के प्रति संवेदनशील और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने वाले नागरिक बन सकती है।

रेलवे परिसरों में स्वास्थ्य सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती, सोलापुर मंडल ने स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों को दिया विशेष प्रशिक्षण

सोलापुर। रेलवे परिसरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में मध्य रेलवे के सोलापुर मंडल ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों के लिए एक दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. कोटनीस मेमोरियल रेलवे अस्पताल, सोलापुर में आयोजित इस विशेष प्रशिक्षण का उद्देश्य निरीक्षकों को नवीनतम स्वास्थ्य मानकों, तकनीकी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक नियमों से अद्यतन करना था, ताकि वे रेलवे परिसरों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकें।

रेलवे प्रशासन का मानना है कि लाखों यात्रियों की दैनिक आवाजाही वाले रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे परिसरों में स्वच्छता तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। मानसून के मौसम में जलजनित और संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य निरीक्षकों की भूमिका और अधिक अहम हो जाती है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सोलापुर मंडल ने यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि निरीक्षकों को आधुनिक कार्यप्रणाली और नवीन दिशा-निर्देशों की जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इस रिफ्रेशर कोर्स में सोलापुर मंडल के 15 मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों एवं स्वास्थ्य निरीक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, रेलवे परिसरों में स्वच्छता प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा, पेयजल गुणवत्ता की निगरानी, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं तथा सरकारी खरीद प्रणाली से संबंधित नवीनतम प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ-साथ रेलवे में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य प्रशासन और स्वच्छता प्रबंधन से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिए। प्रतिभागियों को रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू आचरण नियम, अनुशासन एवं अपील नियमों, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े पहलुओं की जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जल स्रोतों की गुणवत्ता जांचने तथा जलजनित रोगों की रोकथाम के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

प्रशिक्षण में खाद्य सुरक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना स्वास्थ्य निरीक्षकों की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके लिए खाद्य एवं जल के नमूनों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहित करने, सुरक्षित परिवहन और प्रयोगशाला जांच की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार की खाद्यजनित बीमारी की आशंका होने पर किस प्रकार त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों को भी प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया। विशेषज्ञों ने वायु, जल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हुए रेलवे परिसरों में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के उपायों की जानकारी दी। प्रतिभागियों को यह भी बताया गया कि पर्यावरणीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य एक-दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद प्रक्रिया, निविदा प्रणाली और पारदर्शी खरीद व्यवस्था पर भी विशेष सत्र आयोजित किया गया। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को डिजिटल खरीद प्रणाली के लाभ, प्रक्रियाओं और नियमों से अवगत कराया ताकि प्रशासनिक कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

मेलों, त्योहारों और विशेष आयोजनों के दौरान रेलवे परिसरों में बढ़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसे अवसरों पर स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, खाद्य निरीक्षण, कचरा प्रबंधन और रोग नियंत्रण के लिए विशेष निगरानी आवश्यक होती है। प्रतिभागियों को आपातकालीन परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी संचालन के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

रिफ्रेशर कोर्स के दौरान निरीक्षकों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। निवारक स्वास्थ्य उपायों, मलेरिया एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम, स्वच्छता प्रबंधन तथा रेलवे परिसरों में स्वास्थ्य संबंधी मानकों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का विस्तार से अभ्यास कराया गया। अधिकारियों का मानना है कि इससे रेलवे परिसरों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर सोलापुर मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने सभी प्रतिभागियों को रिफ्रेशर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए सभी स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षकों की सराहना करते हुए कहा कि रेलवे में यात्रियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और अनुभव का उपयोग निरीक्षक अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावी ढंग से करेंगे तथा रेलवे परिसरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

पूर्व गृह सचिव का दावा: अयोध्या राम मंदिर को दान की गई सोने की परत चढ़ी रामचरितमानस की पुस्तक गायब है

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी को लेकर चल रहे विवाद के बीच, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय गृह सचिव एस. लक्ष्मीनारायण के एक सनसनीखेज नए आरोप ने हलचल मचा दी है। 1970 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी ने गंभीर आरोप लगाया है कि लगभग डेढ़ क्विंटल वजनी और 800 ग्राम वजनी सोने से जड़ी अत्यंत मूल्यवान श्री रामचरितमानस पोथी, जो उन्होंने मंदिर को दान की थी, मंदिर से गायब हो गई है। उन्होंने अपनी दिवंगत माता के आभूषणों को पिघलाकर इस विशेष पोथी पर सोने की परत चढ़वाई थी और स्थानीय पुलिस की मदद से इसे 8 अप्रैल, 2024 को स्थापित किया था। लेकिन कुछ महीनों बाद यह गायब हो गई।

पूर्व गृह सचिव ने अपना दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जब उन्होंने इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपात्र रॉय से संपर्क किया, तो चंपात्र रॉय का रवैया बेहद उपेक्षापूर्ण था। चंपात्र रॉय ने कहा था कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा ही होगा। यह कहकर एस. लक्ष्मी नारायण को फटकार लगाई गई और रसीद देने से भी इनकार कर दिया गया।

इस संबंध में लगभग 50 व्हाट्सएप संदेश और 12 पत्र लिखने के बावजूद, लक्ष्मीनारायण को न तो कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया मिली है और न ही दान के लिए कोई कानूनी रसीद।

महज दो घंटे में चार इंच बारिश से डूबा सूरत, घुटनों तक पानी में फंसी गाड़ियां; शहर की रफ्तार थमी, सड़कों पर घंटों लगा जाम

सूरत। दक्षिण गुजरात में मानसून ने सोमवार को पूरी ताकत के साथ दस्तक दी और कुछ ही घंटों की मूसलाधार बारिश ने सूरत शहर की रफ्तार थाम दी। शाम चार बजे से छह बजे के बीच मात्र दो घंटे में लगभग 105 मिलीमीटर (करीब चार इंच) बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई प्रमुख इलाके जलमग्न हो गए। मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं, घुटनों तक भरे पानी में वाहन फंस गए और कार्यालयों से घर लौट रहे हजारों लोगों को घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। भारी बारिश ने एक बार फिर शहर की जलनिकासी व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर कर दिया।

जिला फ्लड कंट्रोल रूम के अनुसार सोमवार सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक के 12 घंटों में पूरे सूरत जिले में औसतन 37.17 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सूरत शहर में हुई, जहां कुल 112 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार कम समय में हुई अत्यधिक बारिश के कारण जल निकासी व्यवस्था पर अचानक दबाव बढ़ गया, जिसके चलते कई निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया।

बारिश का सबसे अधिक असर शहर के व्यस्त व्यावसायिक और आवासीय क्षेत्रों में देखने को मिला। अडाजन, सलाबतपुरा, कतारगाम, वराछा, पालनपुर, उधना, पाल, जहांगीरपुरा और अन्य कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। कई स्थानों पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि दोपहिया और चारपहिया वाहन बीच सड़क पर ही बंद हो गए। घुटनों तक भरे पानी में वाहन चालकों को गाड़ियों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा, जबकि कई लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर वाहन खड़े कर बारिश थमने का इंतजार किया।

सबसे अधिक परेशानी उस समय हुई जब बारिश कार्यालयों की छुट्टी के समय शुरू हुई। बड़ी संख्या में कर्मचारी, विद्यार्थी और व्यापारी अपने घरों की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान मुख्य मार्गों पर जलभराव होने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई प्रमुख चौराहों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दीं और लोगों को कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में भी काफी समय लग गया। एक मार्ग पर जाम देखकर लोग वैकल्पिक रास्तों की ओर बढ़े, लेकिन अधिकांश वैकल्पिक सड़कें भी पानी में डूबी होने के कारण वहां भी यातायात बाधित हो गया।

लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की मुख्य सड़कों के अलावा आंतरिक गलियां और निचले इलाके भी जलमग्न हो गए। कई आवासीय क्षेत्रों में पानी घरों और दुकानों के बाहर तक पहुंच गया। कुछ स्थानों पर ड्रेनेज लाइन का पानी बैक होने की शिकायतें भी सामने आईं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हर मानसून में यही स्थिति बनती है और थोड़ी देर की तेज बारिश भी शहर की सामान्य व्यवस्था को प्रभावित कर देती है।

जिला प्रशासन के अनुसार बारिश केवल शहर तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिले के अन्य तालुकों में भी अच्छी वर्षा दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार कामरेज में 84 मिलीमीटर, बारडोली और अंबिका तालुका में 38-38 मिलीमीटर, पलसाना में 35 मिलीमीटर, चोर्यासी में 32 मिलीमीटर, मांगरोल में 26 मिलीमीटर, ओलपाड में 24 मिलीमीटर, महुवा में 18 मिलीमीटर, उमरपाड़ा में 17 मिलीमीटर, अरेथ में 15 मिलीमीटर तथा मांडवी में 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई।

भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी नुकसान की घटनाएं सामने आईं। महुवा तालुका के फुलवाड़ी गांव में सुरेशभाई पटेल के फूस के मकान की छत का पिछला हिस्सा ढह गया। वहीं अंबिका तालुका के बांभणिया गांव में सुमनभाई के पुराने मकान का एक हिस्सा गिर गया। राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

शहर में जलभराव की सूचना मिलते ही सूरत महानगरपालिका की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय हो गईं। कई स्थानों पर नालों और ड्रेनेज लाइनों की सफाई कर पानी की निकासी का प्रयास किया गया। जलभराव वाले क्षेत्रों में कर्मचारियों ने गटर के ढक्कन खोलकर जमा पानी निकालने का काम किया, ताकि यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सके। इसके बावजूद कई इलाकों में देर शाम तक पानी भरा रहा और लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कम समय में अत्यधिक वर्षा होने के कारण किसी भी शहरी जलनिकासी व्यवस्था पर अचानक दबाव बढ़ जाता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि तेजी से फैलते शहरीकरण के साथ जलनिकासी तंत्र को और अधिक आधुनिक एवं सक्षम बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बेहतर ढंग से निपटा जा सके।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। निचले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन तैयार रखे गए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जलभराव वाले क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें, तेज बहाव वाले पानी में वाहन न चलाएं तथा मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का पालन करें।

सोमवार की मूसलाधार बारिश ने यह स्पष्ट कर दिया कि मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिण गुजरात में और बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में प्रशासन के सामने जलनिकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, यातायात प्रबंधन और संभावित आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की बड़ी चुनौती रहेगी, जबकि शहरवासी उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी बारिश के दौर में उन्हें ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।